

# केन्द्रीय आम बजट : 2021-22

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वर्ष लगातार तीसरी बार केंद्रीय बजट-2021 पेश किया। इस वर्ष का बजट पूरी तरह से पेपरलेस रूप में प्रस्तुत किया गया। इस बजट में पूंजीगत व्यय को 2020-21 के 4.39 लाख करोड़ से बढ़ाकर 5.54 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।

## ■ वर्ष 2021-2022 का बजट 6 प्रमुख बिन्दुओं पर आधारित है।

1. स्वास्थ्य और कल्याण
2. वास्तविक और वित्तीय पूंजी, और बुनियादी ढाँचा
3. अकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास
4. मानव पूंजी में नवजीवन का संचार
5. नवोन्मेष और अनुसंधान और विकास
6. न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन

## केन्द्रीय बजट 2021-22 : परीक्षोपयोगी तथ्य

- आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार COVID-19 प्रयासों का समर्थन करने के लिए कुल 27.1 लाख करोड़ रुपए का व्यय तीनों आत्मनिर्भर पैकेज पर हुआ, जोकि सकल घरेलू उत्पाद का 13 प्रतिशत से ज्यादा है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अलावा छह स्तंभों में से पहली आत्मनिर्भर योजना में छह साल में 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा, सरकार 15 स्वास्थ्य आपातकालीन केंद्र भी स्थापित करेगी।
- 2.87 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन की शुरुआत की जायेगी, जिसे पांच वर्षों में घरों को कवर करने के लिए कार्यान्वित किया जाएगा।
- बजट 2021 में मिशन पोषण 2.0 लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा, 1.42 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शहरी 'स्वच्छ भारत मिशन' 2.0 का शुभारंभ किया जाएगा।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वोलंटरी वाहन स्कैपिंग नीति की घोषणा की है। सभी वाहन फिटनेस टेस्ट से गुजरेंगे-जिसकी अवधि यात्री वाहनों के लिए 20 वर्ष और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15 वर्ष है।
- COVID-19 टीकों के लिए 35000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
- सरकार ने 13 क्षेत्रों को कवर करते हुए प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव स्कीम (पीएलआई) के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता जताई। इसके अलावा, 7 टेक्सटाइल पार्क तीन वर्षों में लॉन्च किए जाएंगे।
- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन को 7,400 परियोजनाओं तक विस्तारित किया गया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय इन्फ्रा पाइपलाइन के तहत 1.1 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएँ पूरी की जा चुकी हैं।
- सरकार नई इन्फोटेक परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय परिसंपत्ति मुद्राकरण पाइपलाइन शुरू करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये प्रदान करने वाले DFI की स्थापना के लिए एक विधेयक लाएगी।

- निवेशकों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए एक परिसंपत्ति मुद्राकरण डैशबोर्ड बनाया जाएगा।
- 2021-22 के लिए; पूंजीगत व्यय 5.54 लाख करोड़ रुपये देखा गया है, जो साल-दर-साल 34.5 प्रतिशत है।
- निवेशकों को आकर्षित करने के लिए NHAI ने एक InVit प्रायोजित किया है। इस प्रकार 5000 करोड़ परिचालन मूल्य वाली 5 सड़कें NHAI InVit को हस्तांतरित की जा रही हैं।
- संचालन और प्रबंधन के लिए बहुत से हवाई अड्डों का भी विमुद्राकरण किया जाएगा। टीएआई-2,3 शहरों में एएआई हवाई अड्डों और अन्य रेलवे परिसंपत्तियों का विमुद्राकरण किया जाना है।
- भारतमाला परियोजना के तहत 13000 किमी० से अधिक सड़कें तैयार की गईं।
- 7,000 करोड़ रुपये की पावर ट्रांसमिशन संपत्ति को पावर ग्रिड इनविट को हस्तांतरित किया जाएगा।
- ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि वित्त वर्ष 2021 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.8 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2022 के लिए 6.8 प्रतिशत रहेगा।
- सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ रुपये, केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 65000 करोड़, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 25000 करोड़ रु० आवंटित की जाएगी।
- दिसम्बर 2023 तक ब्रॉड-रेल मार्गों का पूरा, 100% विद्युतीकरण कर लिया जाएगा।
- छोटी कंपनियों की परिभाषा को अपडेट करने के लिए 50 लाख रुपये की शुद्ध संपत्ति से करोड़ों रुपये तक जुटाने का प्रस्ताव है।
- एक लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों में वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए 2217 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।
- अनुपूरक पोषण कार्यक्रम और POSHAN अभियान का विलय, मिशन POSHAN 2.0 का शुभारंभ किया जाना, पोषण संबंधी सामग्री, वितरण और परिणाम को मजबूत करने के लिए, आकांक्षी जिलों में पोषण परिमाणों में सुधार के लिए गहन रणनीति बनाई जायेगी।
- बजट 2021 में, भारतीय रेलवे के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की गई है।
- भारतीय रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड उपलब्ध कराया गया है। कुल खर्च में से 1,07,100 करोड़ रुपये 2021-22 में पूंजीगत व्यय के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।
- सरकार की योजना भारतीय जीवन बीमा निगम में अपनी हिस्सेदारी का हिस्सा बेचने की है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 20000 करोड़ रुपये जुटाने की घोषणा की गई है।
- बीमा क्षेत्र में FDI को अब 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रस्ताव है।



सौर ऊर्जा निगम को 1000 करोड़ रुपये और अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को 1500 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।

जम्मू-कश्मीर के लिए एक नई गैस पाइपलाइन परियोजना की घोषणा की। केंद्र ने सार्वजनिक बसों के लिए 18000 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है।

धान किसानों को भुगतान की गई कुल राशि 2020-21 में 1.72 लाख करोड़ रुपये हो गई।

सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभों को अतिरिक्त 1 करोड़ लोगों तक पहुंचाने की घोषणा की है। यह योजना वर्तमान में 12 करोड़ परिवारों को लाभान्वित करती है, को स्वच्छ पेयजल ईंधन प्रदान करने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।

50 लाख रुपये की मौजूदा सीमा से पूंजी आधार को 2 करोड़ रुपये तक बढ़ाकर छोटी कंपनियों की परिभाषा को संशोधित किया जाएगा।

1 अप्रैल, 2021 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के लिए विनिवेश रसीदें 1.75 लाख करोड़ रुपये रखी गई हैं।

सरकार ने 'संशोधित', सुधार-आधारित, परिणाम-आधारित बिजली वितरण क्षेत्र योजना शुरू करने की दिशा में बजट में करीब 3.60 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 15000 से अधिक स्कूलों को गुणात्मक रूप से मजबूत किया जाएगा।

डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।

गोवा सरकार को पुर्तगाली से राज्य की मुक्ति की जयंती समारोह के लिए 300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ को बढ़ाया जाएगा। यह भारत में परिवहन (उबर और ओला), खाद्य वितरण (स्विगी और जोमाटो) जैसे क्षेत्रों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदाताओं और आईटी और सॉफ्टवेयर फर्मों में अनुबंध श्रमिकों के अलावा लगभग 15 मिलियन गिग श्रमिकों को प्रभावित करेगा।

बंगाल, असम के चाय श्रमिकों के लिए 1000 करोड़ रुपये की घोषणा।

वित्त वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 9.5% जबकि 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.8% अनुमानित है।

आगामी जनगणना भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए वर्ष 2021-2022 में 3768 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

वित्त वर्ष 2021 में 30000 करोड़ रुपये से ग्रामीण इंफ्रा डेवलपमेंट का आवंटन बढ़ाकर अगले वित्त वर्ष के लिए 40000 करोड़ रुपये हो गया।

5 प्रमुख मत्स्य पालन केंद्रों के विकास की घोषणा की गई।

1000 और मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय बाजार के साथ एकीकृत किया जाएगा।

केंद्रीय विश्वविद्यालय लेह, लद्दाख में स्थापित किया जाएगा।

22 और खराब होने वाली वस्तुओं को कवर करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना है।

■ उद्यमी क्षमता वाले अनिवासी व्यक्ति अब 182 दिनों से 120 दिनों तक पूंजीकरण समय को कम करते हुए, बिना किसी भुगतान पूंजी और टर्नओवर प्रतिबंधों के साथ एक व्यक्ति कंपनियों (ओपीसी) को स्थापित करने में सक्षम हैं।

■ इस बार के बजट में आम करदाताओं के टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है।

■ रिटर्न फाइल 2014 के 3.3 करोड़ से लगभग दोगुना बढ़कर 2020 में 6.48 करोड़ हो गया।

■ सरकार ने 75 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता को हटाकर वरिष्ठ नागरिकों को राहत दी है।

■ वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जिनके पास केवल पेंशन और ब्याज आय है, उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने की छूट का प्रस्ताव किया गया है।

■ आय को छिपाने के साक्ष्य के साथ गंभीर कर चोरी के मामले को फिर से खोलने की समय सीमा 6 साल से घटाकर 3 साल की गई।

■ एक वर्ष में 50 लाख रुपये या उससे अधिक के लिए यह अवधि प्रावधान 10 वर्षों तक की होगी।

■ 50 लाख रु० तक और 10 लाख आय रु० तक के करदाताओं की कर योग्य आय के लिए विवाद समाधान समिति नेशनल फेसलेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल सेंटर की स्थापना की जाएगी।

■ 1 लाख से अधिक करदाताओं ने 85,000 करोड़ रुपये के कर विवादों को निपटाने के लिए 30 जनवरी, 2021 तक विवाद से विश्वास योजना का विकल्प चुना।

■ सस्ते घर खरीदने के लिए मिलने वाले ऋण के ब्याज में 1.5 लाख रुपये तक की छूट का प्रावधान 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

■ स्कूलों और अस्पतालों को चलाने वाले छोटे चैरिटेबल ट्रस्टों के लिए वार्षिक रसीद की छूट सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी गई है।

■ टैक्स ऑडिट की सीमा 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ रुपये हो गई है।

■ पांच वर्षों में सरकार ने 4000 करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय के साथ गहरे महासागर मिशन का प्रस्ताव किया है।

■ नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारी के पीएफ में योगदान की देर से जमा को नियोक्ता को कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी।

■ स्टार्ट-अप के लिए कर में छूट के दावे की पात्रता एक और वर्ष बढ़ाई गई।

■ 31 मार्च, 2022 तक स्टार्ट-अप में निवेश के लिए पूंजीगत लाभ में छूट

■ प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी योगदान की देर से जमा के लिए नियोक्ताओं को कोई कटौती नहीं।

■ छोटी कंपनियों की अनुपालन आवश्यकताओं को आसान बनाया जाएगा।

■ श्रेयोल्ड शेयर पूंजी 2 करोड़ रु० और 20 करोड़ रु० के कारोबार वाली छोटी कंपनियाँ होंगी।

■ गैर-सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों और राज्यों की साझेदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे।

■ 2021-22 के बजट में सोने और चांदी पर सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बनाया जाएगा।

■ कपास पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 10% से 15% कर दिया गया है।

■ सौलर लालटेन पर सीमा शुल्क में 5% की कटौती।

■ कॉपर स्ट्रैप पर ड्यूटी 5% से घटकर 2.5%